



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1945 (श10)
(सं0 पटना 110) पटना, शुक्रवार, 9 फरवरी 2024

सं0 E2-1-1/2023-694
निर्वाचन विभाग

संकल्प

09 फरवरी, 2024

विषय:— आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु Election Personnel Management Information System (EPMIS) द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्य करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के तहत नामांकन के आधार पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्रालय के National Informatics Centre, Patna बिहार इकाई के Digital Government Research Centre, Patna द्वारा तैयार परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए NICS (National Informatics Centre Services Incorporated) को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति।

17वीं लोक सभा का कार्यकाल जून, 2024 में समाप्त हो रहा है। उसके पूर्व लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराया जाना है तथा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 भी सम्पन्न कराया जाना है। निर्वाचन में कार्मिकों का डाटाबेस का रख-रखाव एवं उसका उपयोग ऑनलाईन किया जा रहा है। डाटाबेस का प्रबंधन NIC के तैयार सॉफ्टवेयर Election Personnel Management Information System (EPMIS) के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस कार्मिकों का भी डाटाबेस एवं मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त Force Deployment S/W से किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचन संबंधी गतिविधियों यथा Web, Mobile, GIS एवं अन्य तकनीक द्वारा 1. Development/Customization of EPMIS, Force Deployment S/W & Ele-Traces App Support at State level (during the first 24 Months) 2. Security Audit of Application [Mandatory for hosting and rolling out applications] के कार्यान्वयन किये जाने पर प्रभावी अनुश्रवण कर सकती है।

2. वर्तमान में लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की गतिविधियों यथा 1. Development/Customization of EPMIS, Force Deployment S/W & Ele-Traces App Support at State level (during the first 24 Months) का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन किए जाने हेतु NIC, Patna, Bihar के अधीन Digital Government Research Centre, Patna उप महानिदेशक के

पत्रांक 178/2024 दिनांक 08.01.2024 से Election Personnel Management Information System (EPMIS), Force Deployment S/W & Ele-Traces (EPMIS), का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भारत सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्रालय के National Informatics Centre, Patna बिहार इकाई के द्वारा समर्पित परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए NICS (National Informatics Centre Services Incorporated) अधिकृत किया गया है। परियोजना का नाम Customisation and Implementation of EPMIS, Force Deployment S/W & Ele-Traces (EPMIS) नामित है। यह परियोजना दो भागों में है, जो निम्नवत् है :-

Part – A

1. Cost for Development/Customization of EPMIS, Force Deployment Software and Ele-Traces App Support (during the first 24 Months)	Rs. 38,76,000/-
2. Hardware, AMC & Support	Rs. 3,58,000/-
3. Misc. Expenses and Contingencies.	Rs. 2,50,000/-
Total:	Rs. 44,84,000/-
NICS@9% Service Charge Payable	Rs. 4,03,560/-
GST@18% Payable	Rs. 8,79,760/-
Grand Total	Rs. 57,67,320/-
(Rupees Fifty Seven Lakh Sixty Seven Thousand Three Hundred Twenty Only.)	

Part – B

1. Security Audit of Application [Mandatory for hosting and rolling out applications]	Rs. 2,50,000/-
NICS@9% Service Charge Payable	Rs. 22,500/-
GST@18% Payable	Rs. 49,050/-
Grand Total	Rs. 3,21,550/-
(Rupees Three Lakh Twenty On Thousand Five Hundred Fifty Only.)	

4. भारत सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्रालय के NIC बिहार इकाई के Digital Government Research Centre, Patna द्वारा तैयार परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए NICS की अनुशंसा की गयी है। NICS एक भारत सरकार का उपक्रम है, जो NIC के तकनीकी निदेशन में कार्य सम्पादित कराती है। आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु Election Personnel Management Information System (EPMIS)/Force Deployment S/W & Ele-Traces App द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्य करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर NICS द्वारा कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से लोकसभा आम निर्वाचन एवं विधान सभा आम निर्वाचन दोनों वर्ष में कार्य कराये जायेंगे, जिस कारण से इस पर होने वाले व्यय केन्द्र एवं राज्य दोनों से वहन किया जायेगा।

5. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) में नामांकन द्वारा बाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि – “किसी आपवादिक स्थिति में विशेष रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य बाह्य स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं। वैसे मामलों में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को बाह्य स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विशेष हित या उद्देश्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।”

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत National Informatics Centre, Patna के अधीन Digital Government Research Centre, Patna से प्राप्त Election Personnel Management Information System (EPMIS) अन्तर्गत परियोजना 1. Development/Customization of EPMIS, Force Deployment S/W & Ele-Traces App Support at State level (during the first 24 Months) 2. Security Audit of Application [Mandatory for hosting and rolling out applications] पर कुल ₹ 60,88,870/- (साठ लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ सत्तर) मात्र व्यय पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के अंतर्गत नामांकन के आधार पर NICS (National Informatics Centre Services Incorporated) को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। उक्त राशि का व्यय का विकलन वर्ष 2024 में मांग संख्या 06, मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन 00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष

0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 एवं वर्ष 2025 में मांग संख्या 06, मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष 00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार उपशीर्ष-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 कार्यालय व्यय से किया जायेगा।

6. आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु Election Personnel Management Information System (EPMIS) Force Deployment S/W & Ele-Traces App द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्य करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए भारत सरकार का उपक्रम NICSI (National Informatics Centre Services Incorporated) को प्राधिकृत करने की अनुमति तथा कंडिका 3, 4 एवं 5 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.02.2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
(हो) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 110-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>